



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23—जुलाई 29, 2005 (श्रावण 1, 1927)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23—JULY 29, 2005 (SRAVANA 1, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ	भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ
825	भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
689	भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
7	भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
1161	भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	भाग III--खण्ड-1--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	853
*	भाग II--खण्ड-1--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	347
*	भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रबल समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
*	भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक नियमों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1921
*	भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	201
*	* अंकड़े प्राप्त नहीं हुए।	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

CONTENTS

Page	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	825
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	689
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1161
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	853
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	347
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1921
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	201
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1].

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 जुलाई 2005

संकल्प

सं. 11011/5/2003-रा. भा. (अनु.)--संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन 1976 में गठित की गई, थी। समिति द्वारा सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी में लेखन कार्य, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति, सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, सरकारी कामकाज में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिन्दी में उपलब्धता, राज्यों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिन्दी, कंप्यूटरीकरण एक चुनौती से संबंधित प्रतिवेदन का सातवां खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई थी। इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति को प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निर्देश हुआ है :

क्र. सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
16.5 (क)	केंद्रीय हिन्दी समिति का पुरान्गठन निश्चित समय पर प्रत्येक तीन वर्ष पर अवश्य किया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि केंद्रीय हिन्दी समिति का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसका कार्यकाल बढ़ाया अथवा कम भी किया जा सकता है।
16.5 (ख)	केंद्रीय हिन्दी समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित करने के प्रयास किए जाएं और समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को तत्परता से लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग केंद्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए तत्परता से आवश्यक कारबाई करें।
16.5 (ग)	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष तथा तीनों उपसमितियों के संयोजकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बल सरकारी अधिकारियों की समिति है। अतः यह संस्तुति स्वीकार्य नहीं पाई गई।

16.5 (घ)	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को सक्रियता से लागू किया जाए। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पांच खंडों पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.5 (घ)	हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन सही समय पर होना चाहिए तथा बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति का गठन/पुनर्गठन समय पर करे और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें करे।
16.5 (इ)	हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों को कार्यसूची में संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों में केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति की प्रगति के लिए एक मद जोड़ी जाए तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों पर शीघ्र तथा समुचित रूप से कार्रवाई की जाए ताकि हिंदी सलाहकार समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके तथा राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित हो सके।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।
16.5 (ज)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रधान को स्वयं उपस्थित होना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, उपक्रमों और बैंकों आदि कार्यालयों के प्रमुखों को निर्देश दें कि वे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्वयं भाग लें।
16.5 (झ)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की उच्च स्तर पर पूर्ण निष्ठा से निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख समिति के निर्णयों पर कार्यवाही की निगरानी व समीक्षा सुनिश्चित करें।
16.5 (ट)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाएं तथा वर्ष में आयोजित होने वाली चार बैठकों में से कम से कम दो बैठकों में कार्यालय के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से स्वयं भाग लें और बैठकों में लिए गए निर्णयों का पूर्ण रूप से अपने कार्यालयों में अनुपालन कराएं।	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में दो बैठकें अपेक्षित हैं। इन बैठकों में कार्यालय अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भाग लें। इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित निर्देश जारी करें।

16.5 (ठ)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में तीन बैठकें समिति के अध्यक्षों की अध्यक्षता में अलग-अलग कार्यालयों में आयोजित की जाए तथा अंतिम बैठक समिति के अध्यक्ष के कार्यालय में ही आयोजित की जाएं और उसमें राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें ताकि वर्ष भर की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जा सके और पाई गई कमियों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें सामूहिक प्रयास से दूर कर लिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार्य नहीं पाई गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अलग-अलग स्थानों पर आयोजित करना, बैठक स्थान व अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।
16.5 (ड)	विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बड़ी सदस्य संख्या को देखते हुए ऐसे नगरों में जहां एक ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तीन उप समितियों में विभाजित कर तीन अलग-अलग संयोजक बनाए जाएं एवं उनका अध्यक्ष एक ही हो ताकि सभी सदस्य कार्यालयों में हिंदी के अनुकूल वातावरण बने और राजभाषा नियमों के प्रति जागरूकता आए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-६ में की गई संस्तुति सं. 11.5.17 पर आदेश दिया गया है कि ऐसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को, जिनकी सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक है, दो भागों में बांटा जाए। इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन करना सामयिक नहीं है।
16.5 (ढ)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा समारोह/संगोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए ताकि राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा हो और अनुकूल वातावरण बने।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.5 (त)	प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन होना चाहिए तथा नियमित रूप से बैठकें तिमाही आयोजित की जानी चाहिए। अगली तिमाही बैठक में पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति के पूर्ण और अपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.5 (थ)	राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों के अभिलेख रखे जाने चाहिए तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों को पूर्ण निष्ठा एवं तत्परतापूर्वक लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.6 (क)	राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर देश के भीतर एवं बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/संगोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति सिद्धांतः स्वीकार कर ली गई है। सभी कार्यालय अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्यक्रम, संगोष्ठी आदि आयोजित करें।

16.6 (ख)	<p>सभी सरकारी कार्यालयों में पुस्तकालय/बुक क्लब आदि की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हिंदी का सरल, सुबोध व रुचिकर साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पाठकों को हिंदी के पठन-पाठन के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्हें उचित अवसरों पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिए जाने वाले पुरस्कारों की न्यूनतम राशि एक हजार रुपये की जानी चाहिए और पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।</p>	<p>यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी कार्यालय अपने पुस्तकालय अनुदान की राशि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च करे और अपने कार्मिकों को उनके पठन-पाठन के प्रति प्रेरित करे। पुरस्कारों की राशि और संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।</p>
16.6 (ग)	<p>विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रकाशनों की कमी महसूस न हो इसके लिए संबंधित विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लिखने वाले लेखकों को आकर्षक पुरस्कार दिये जाने चाहिए, साथ ही पुस्तक की उपयोगिता को देखते हुए समुचित रायलटी देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।</p>	<p>यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/ विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें।</p>
16.7 (क)	<p>हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करवाने के लिए राजभाषा विभाग कोई पाठ्यक्रम तैयार करें एवं उचित व्यवस्था हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से ठोस कदम उठाएं।</p>	<p>यह संस्तुति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से एक समुचित पाठ्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करें।</p>
16.7 (ख)	<p>गैर सरकारी प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशनों के प्रकाशन की अनुमति देते समय यह पाबंदी अवश्य लगाई जाए कि वे केवल अंग्रेजी भाषा में उन्हें प्रकाशित न करें बल्कि इन प्रकाशनों को डिग्लाट में हिंदी-अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से छापें।</p>	<p>यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लाट रूप में छपवाया जाए।</p>
16.7 (ग)	<p>प्रत्येक स्तर पर हिंदी के और पदों का सृजन किया जाए।</p>	<p>यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग व सभी कार्यालय न्यूनतम हिंदी पदों के संबंध में जारी आदेशों का सरकार के संगत आदेशों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें।</p>
16.7 (घ)	<p>अवर सचिव व इसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों की प्रबंधकीय दक्षता के उन्नयन हेतु आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षणों को हिंदी में आयोजित किया जाए।</p>	<p>यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षणों को प्रमुखतः हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणतः मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।</p>

16.7 (च)	केंद्रीय सेवाओं आदि में कार्यरत अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएं जिनमें व्याख्यान देने के लिए विश्वविद्यालयों के प्रस्थान हिंदी के विद्वानों अथवा अपने विषय को हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करने में सक्षम विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। कार्यशालाओं में प्रस्थान हिंदी के विद्वानों और सक्षम विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए।
16.7 (छ)	अधिकारियों के लिए उनके द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन व अन्य कार्यों के लिए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तथा उनका अभिलेख (लेखा-जोखा) रखना अनिवार्य किया जाए तथा मुख्यालय/मंत्रालय स्तर पर इसकी समीक्षा सुनिश्चित की जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जिन अधिकारियों के पास हिंदी आशुलिपिकों की सुविधा उपलब्ध है वे उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग करें। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा हिंदी में दी जाने वाली डिक्टेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
16.8 (क)	विधायी विभाग, हिंदी में मूल प्रारूपण के संबंध में प्रशिक्षण के काम को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप में तीन माह के भीतर आरंभ करवाएं ताकि विधि प्रारूपण का कार्य मूल रूप से हिंदी में हो सके।	इसी प्रकार की संस्तुति संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-5, सिफारिश संख्या 10 में की गई थी। उस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हुए आदेश पारित किए गए थे कि "विधायी विभाग विधि विशेषज्ञों/प्रारूपकारों को विधिक सामग्री का मूल प्रारूपण हिंदी में करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।" विधायी विभाग इस संस्तुति के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करे।
16.8(ख)	इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण कार्य छह माह से एक वर्ष की समयावधि में पूरा किया जाए। प्रशिक्षण कार्य की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर विधायी प्रारूपण का कार्य हिंदी में प्रारंभ किया जाए। इस प्रयोजन के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जाए।	यह संस्तुति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। विधायी विभाग इसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें।
16.8 (ग)	राजभाषा हिंदी में प्रारूपण करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि प्रारूपकार नियमित सरकारी कर्मचारी हैं।

16.8 (घ)	संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन किया जाए ताकि विधायी विभाग मूल प्रारूपण का कार्य हिंदी में कर सके।	
16.8 (च)	संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन के उपरांत उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय से कहा जाए कि वे निर्णय और डिक्री आदि हिंदी में देना प्रारंभ करें ताकि ऐसे अनेक विभाग जो न्यायिक/अर्धन्यायिक स्वरूप के कार्य कर रहे हैं, न्याय-निर्णयन हिंदी में कर सकें। इस समय ऐसे विभाग न्याय-निर्णयन हिंदी में पारित करने में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में उनके निर्णयों के विरुद्ध की जाने वाली अपील अंग्रेजी में होती है।	(घ) और (च): ये दोनों संस्तुतियां विधायी विभाग को इस निर्देश के साथ भेज दी जाए कि वे इन पर भारतीय विधि आशोग की सलाह लेकर अपनी सुविचारित टिप्पणी से अवगत कराएं। तदनुसार ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
16.9 (क)	किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए जो न केवल संसदीय राजभाषा समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित रहेंगे बल्कि केंद्रीय हिंदी समिति के भी स्थायी सदस्य रहेंगे। इसके लिए हिंदी के किसी विद्वान् या हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़े व अनुभवी व्यक्ति की सेवाएं लेना उचित होगा।	यह संस्तुति विचारधीन है।
16.9 (ख)	सरकारी कार्यालयों में मूल रूप से हिंदी में दैनिक नेमी काम हो सके, इसके लिए उच्च अधिकारी वर्ग को हिंदी में प्रशिक्षित किया जाए। राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव एवं उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं को आयोजन करें। मंत्रालयों/विभागों के बाद संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों के उच्च अधिकारियों के लिए भी उसी प्रकार कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि मानसिकता में बदलाव आ सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारियों का इन कार्यशालाओं में भाग लेना अनिवार्य हो।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।

16.10	<p>सरकारी कार्यालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों से संबंधित विभिन्न संकलनों, नियमावलियों एवं प्रक्रिया साहित्य के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रकाशनों की हिंदी में सुलभता के लिए संसदीय राजभाषा समिति यह सिफारिश करती है कि :</p>	
16.10(1)	<p>प्राइवेट प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशन छापने के पूर्व उन्हें सरकार द्वारा प्रकाशन के अधिकार (कापीराइट) की अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा प्रावधान पहले से विद्यमान है तो सरकार अथवा इसके किसी विभाग द्वारा कापीराइट हस्तांतरित करने की अनुमति देने के समय संबंधित सामग्री को द्विभाषी मुद्रित कराने की शर्त का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि पुस्तक के आकार के कारण डिग्लाट रूप में छापना असुविधाजनक हो तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के आवरण पृष्ठ पर विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाए कि प्रकाशक/वितरक के पास इस संस्करण का हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध है।</p>	<p>यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लाट रूप में छपवाया जाए।</p>
16.10(2)	<p>भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन एक अतिरिक्त प्रकोष्ठ का गठन करके उसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे :-</p> <p>(क) यह प्रकोष्ठ सभी मंत्रालयों/विभागों के सरकारी प्रकाशनों के मौलिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन आदि के कार्य में समन्वय स्थापित करेगा तथा इस प्रकार प्रकाशित साहित्य की सर्कसुलभता सुनिश्चित कराएगा।</p> <p>(ख) विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों में हिंदी प्रकाशनों की कमी को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करेगा एवं इस क्षेत्र में मौलिक लेखन एवं अन्य भाषाओं में उपलब्ध आवश्यक सामग्री का हिंदी में स्तरीय अनुवाद करने का कार्य सुनिश्चित करेगा।</p>	<p>(क) से (च): ये संस्तुतियां विचारकीय हैं।</p>

	<p>(ग) यह प्रकोष्ठ समस्त सरकारी प्रकाशनों को वर्गीकृत करते हुए एक सूची का संकलन करेगा तथा नियमित रूप से इसका प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त नवीन हिंदी प्रकाशनों की उपलब्धता तथा इसके स्रोतों की जानकारी देते हुए इसमें संशोधनों आदि की ताजा जानकारी उपलब्ध कराते हुए एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करेगा।</p> <p>(घ) प्रकोष्ठ अपने इस प्रयोजन के लिए एक वेबसाइट निर्मित कराएगा तथा इसपर सरकारी प्रकाशनों की उपलब्धता के साथ-साथ हिंदी के प्रसार एवं प्रचार से संबंधित बाजार में विभिन्न सॉफ्टवेयरों की जानकारी आदि प्रदान करेगा।</p> <p>(च) यह प्रकोष्ठ मंत्रालयों/विभागों सरकारी उपक्रमों में हिंदी प्रकाशनों को उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव मदद एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा।</p>	
16.10(3)	राजभाषा नीति के कारगर अनुपालन हेतु समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तिका का अद्यतन संस्करण हर दो वर्ष में प्रकाशित करे तथा इसके परिचालन एवं वितरण की ठोस योजना सुनिश्चित करे ताकि राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश एवं इनके संकलन सरकार के सभी छोटे-बड़े कार्यालयों में उपलब्ध हो सके।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.10(4)	समिति का यह भी सुझाव है कि सरकार प्रकाशन विभाग की मौजूदा कार्यप्रणाली की गहराई से समीक्षा करे तथा इसे राजभाषा नीति के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए समुचित उपाय करे।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में राजभाषा विभाग और प्रकाशन प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करें।
16.10(5)	निजी प्रकाशनों की तरह सरकारी प्रकाशन समय-समय पर किए गए संशोधनों/परिवर्तनों को शामिल करते हुए इनके नये संस्करण शीघ्र प्रकाशित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त संकलनों की बिक्री की परवाह किए बिना समयबद्ध प्रकाशन निकाला जाए। इन्हें प्रकाशित करते का दायित्व उन संबंधित मंत्रालयों/विभागों पर हो जो इनका निर्धारण करते हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सरकारी प्रकाशनों के संशोधित एवं अद्यतन संस्करण कई वर्षों के	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में सभी मंत्रालय समुचित कार्रवाई अग्रता के आधार पर सुनिश्चित करें।

	बाद पुनर्मुद्रित किए जाते हैं जिससे इनकी उपादेयता सिद्ध नहीं हो पाती, परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालय पूरी तरह प्राइवेट प्रकाशनों पर निर्भर रहते हैं। इस स्थिति का समाधान खोजा जाना चाहिए एवं अद्यतन प्रकाशन/मुद्रण हेतु एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।	
16.10(6)	प्रकाशनों की सुपाठ्यता आदि को ध्यान में रखते हुए इनके आकर्षक मुख्य पृष्ठ/मुद्रण के लिए अच्छे फान्ट, उत्तम गुणवत्ता वाले पृष्ठ एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इन्हें विभिन्न साइजों में तैयार करने के लिए प्रचलित नीति में व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में सभी मंत्रालय विशेष रूप से शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन प्रभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
16.10(7)	सरकारी प्रकाशनों की सुलभ उपलब्धता के लिए इनका समयबद्ध प्रकाशन किया जाए। इनके बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए एवं वर्तमान नीति में आवश्यक बदलाव करते हुए इस कार्य में निजी पुस्तक विक्रेताओं/एजेंसियों की सहायता ली जाए। सरकारी साहित्यों के हिंदी अनुवाद, प्रेकाशन एवं इनके वितरण में आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए ताकि इनकी उपलब्धता मंत्रालयों/विभागों से लेकर छोटे से छोटे कार्यालयों में भी सुनिश्चित हो सके।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में सभी मंत्रालय विशेष रूप से राजभाषा विभाग और प्रकाशन नियंत्रक, शहरी विकास मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
16.11(क)	समिति ने पाया है कि लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में माध्यमिक स्तर तक हिंदी की पढ़ाई जारी है। समिति की सिफारिश है कि इसे जारी रखा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय हिंदीतर भाषी राज्यों में भाष्यमिक स्तर तक हिंदी की पढ़ाई को जारी रखने की समुचित कार्रवाई करें।
16.11(ख)	अहिंदी भाषी संघ शासित क्षेत्रों में हिंदी का स्तर ऊंचा उठाने के लिए समुचित प्रयास किये जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर आवश्यक कार्रवाई करें।
16.11(ग)	"ख" एवं "ग" क्षेत्रों में स्थित सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में हिंदी की शिक्षा प्राथमिक स्तर से आरंभ कर दसवीं कक्षा तक अनिवार्य की जाए। हिंदी विषय में निर्धारित अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना आवश्यक माना जाए। बारहवीं कक्षा तक हिंदी को	यह संस्तुति सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। शिक्षा विषय समवर्ती सूची में है इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी राज्य सरकारों से परामर्श करके समुचित कार्रवाई करें।

	एक ऐच्छिक शिष्य के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। अगली पंचवर्षीय योजना में हिंदी की शिक्षा का यथोचित प्रावधान किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इसके लिए समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाए।	
16.11(घ)	"क", "ख" तथा "ग" क्षेत्रों की राज्य सरकारों तथा राज्य और संघ सरकार के बीच आपसी पत्राचार आदि की भाषा के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.11(ङ.)	अहिंदी भाषी राज्यों, जहां विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग नहीं हैं, में उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु हिंदी विभाग खोले जाएं। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान अयोग द्वारा पहल की जाए।	यह संस्तुति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार करें।
16.12(क)	विनिवेश के संदर्भ में समिति यह सिफारिश करती है कि जिस भी उपक्रम में सरकारी भागीदारी हो, चाहे कम या ज्यादा, राजभाषा नीति यथावत लागू रहेगी।	इस संस्तुति पर राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालयों से चर्चा करें।
16.12(ख)	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ रवदेशी कंपनियों, जो अपने उत्पाद की बिक्री अथवा उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं, उनके लिए यह बाध्य किया जाए कि वे सरकार के साथ पत्राचार हिंदी में ही करें साथ ही सरकार भी उनके साथ पत्राचार हिंदी में ही करे।	राजभाषा विभाग इस विषय में संबंधित पक्षों से चर्चा करें।
16.12(ग)	भारतीय उत्पादों को विदेशों में उनकी बिक्री के लिए विदेशी भाषा के साथ हिंदी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए।	यह संस्तुति सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है।
16.13(क)	चूंकि कंप्यूटर पर अंग्रेजी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक दो सप्ताह में कंप्यूटर पर हिंदी का प्रशिक्षण दिया जा सकता है अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को दो वर्ष की समय-सीमा में कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाए।	इस संस्तुति का अनुपालन करने का सभी मंत्रालय प्रयास करें।

16.13(ख)	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में एक "सूचना प्रौद्योगिकी मिशन" स्थापित किया जाए, जो हिंदी सॉफ्टवेयर के संबंध में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं पर कार्य करे। यह "सूचना प्रौद्योगिकी मिशन" कांप्लेक्स नेटवर्क प्रणाली का उपयोग कर रहे भारत सरकार के अन्य विभागों जैसे रेल, डाक-तार, बैंक, दूरसंचार, नागर विमानन, विद्युत आदि के साथ समन्वय करे ताकि वे भी अपना विशिष्ट सॉफ्टवेयर पैकेज हिंदी में विकसित कर सके।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे।
16.13(ग)	यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत सरकार के सभी विभागों में केवल वही सॉफ्टवेयर लगाया गया है तथा उपयोग में लाया जा रहा है जिसका हिंदी में उपयोग किया जा सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक प्रभुख भूमिका अदा करे।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार कॉर्सिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

मदन लाल गुप्ता
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 जुलाई 2005
(पुरातत्व)

सं. एफ. 9/4/2004-ई.ई. (सी.ए.बी.ए.)--भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संकल्प सं. एफ. 9/4/2004-ई.ई. (सी.ए.बी.ए.), दिनांकित 29.03.2005 के अनुसरण में, निम्नांकित सदस्यों को केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का सदस्य होने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है :--

1. प्रोफेसर सूरजभान, पूर्व प्रोफेसर, पुरातत्व, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 1817, एच. बी. कालोनी, सेक्टर 1, रोहतक (हरियाणा)
2. प्रोफेसर डॉ. मंडल, पूर्व प्रोफेसर, पुरातत्व, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 9/33, लूथर रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

3. श्री सीताराम राय, पूर्व निदेशक, पुरातत्व, बिहार सरकार, नेहरू नगर, पटना (बिहार)

सौ. आबू राजीब
महानिदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)
New Delhi-110 003, the 8th July 2005

RESOLUTION

No. 11011/5/2003-OL (Research).—

The Committee of Parliament on Official Language was constituted in 1976 under section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. The Committee submitted seventh part of its Report, relating to propagation of Hindi for official purposes, the position of Hindi in the field of Law, original use of Hindi in Government work, availability of publications relating to Administration and Finance in Hindi, position emerging after discussions with the representatives of States and Union Territories, the status of Hindi in the perspective of Globalization and the challenge of computerization to Hindi, to the President. In accordance with section 4(3) of the Official Languages Act, 1963, the Report was laid on the Table of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Copies of the Report were sent to all Ministries/ Departments of the Government of India and to all States/ Union Territory Governments. After considering the views expressed by various Union Ministries/ Departments and the States/ Union Territories Governments, it has been decided to accept most of the recommendations of the Committee in toto and some of them with modifications. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under section 4(4) of the Official Languages Act, 1963 on the recommendations made in the Report of the Committee as follows:

S. No	Recommendations of the Committee	Decision
16.5 (a)	The Kendriya Hindi Samiti must be reconstituted every 3 years on schedule.	This recommendation has been accepted with the modification that the term of Kendriya Hindi Samiti will generally be 3 years but in special circumstances it may be extended or curtailed.
16.5 (b)	Necessary steps should be taken to convene annual meetings of the Kendriya Hindi Samiti regularly under the Chairmanship of the Prime Minister. All decisions taken in the meetings of the Kendriya Hindi Samiti must be implemented.	This recommendation has been accepted. All Ministries/ Departments are requested to take appropriate action to implement the decisions of Kendriya Hindi Samiti.
16.5 (c)	The Deputy Chairman and all 3 conveners of Sub-Committees of the Committee of Parliament on Official Language should be called as special invitees to the meetings of the Central Official Language Implementation Committee.	Central Official Language Implementation Committee is a Government officials committee, hence the recommendation has not been found acceptable.

16.5 (d)	Decisions taken in the meetings of the Central Official Language Implementation Committee should be properly implemented and implementation of the orders of the Hon'ble President on the first five parts of the Report of the Committee of Parliament on Official Language should also be reviewed.	This recommendation has been accepted.
16.5 (e)	Constitution/ reconstitution of the Hindi Salahkar samitis should be done in time and their meetings should be held regularly.	This recommendation has been accepted with the modification that all Ministries/ Departments are to constitute/reconstitute the Hindi Advisory Committee well in time and organize its meetings as per the targets fixed in the Annual Programme.
16.5 (f)	The agenda of the Hindi Salahkar Samiti should include an item regarding review of progress made in the implementation of Official Language Policy in the organization under the administrative control of the concerned Ministry/ Department and proper and immediate action should be taken on the decisions taken by the samiti so that the purpose of constituting Hindi Salahkar Samiti is fulfilled and the progressive use of Union Government's Official Language Hindi could be ensured.	This recommendation has been accepted. All Ministries/ Departments are requested to take necessary action in this regard.
16.5 (g)	Heads of Offices must themselves attend meetings of the Town Official Language Implementation Committee.	This recommendation has been accepted. All Ministries/ Departments are requested to issue instructions to the Heads of their Attached/ Subordinate offices, autonomous bodies, undertakings and banks etc. to attend Town Official Language Implementation Committee meetings personally.
16.5 (h)	The Head of the Office and other senior functionaries should oversee the implementation of the decisions taken in the Town Official Language Implementation Committee's meetings with sincerity.	This recommendation has been accepted. Heads of Office of all member offices of the Town Official Language Implementation Committee are requested to ensure monitoring and review of follow up action of decisions taken by the committee.
16.5 (i)	Quarterly meetings of the Town Official Language Implementation Committee should be held and the heads of Offices must themselves attend at least two meetings out of four and take measures to ensure strict compliance of the decisions taken in these meetings in their offices.	Two meetings of Town Official Language Implementation Committee are required to be held in a year. Heads of Office of all member offices may attend these meetings compulsorily. Department of Official Language may issue instructions in this regard.

16.5 (j)	Three meetings of the Town Official Language Implementation Committee in a year should be held in different offices under the Chairmanship of the Head of the Committee and the last meeting should be held in the office of the Head of the Committee itself and a senior officer of the Deptt. of Official Language should also be invited to attend that meeting, so that a review regarding the activities and progress made through out the year could be undertaken and the shortcomings observed should be brought to the notice of all concerned; and these should be overcome by a collective effort.	This recommendation has not been found acceptable. To organize Town Official Language Implementation Committee meetings at different venues is not feasible from the point of view of availability of venue and other resources.
16.5 (k)	Keeping in view the large number of members of various Town Official Language Implementation Committees in the cities where only one Town Official Implementation Committee exists, such Town Official Language Implementation Committee should be divided into three sub-committees under separate conveners under the Chairman, so that a pro-Hindi atmosphere should be created and awareness of the Official Language Rules etc. in all the member offices increased.	It has been ordered on the recommendation No. 11.5.17 of the VIth report of the Committee of Parliament on Official Language that all such Town Official Language Implementation Committees may be divided into two, where members are 150 or more. It is not appropriate to change the set up at this stage.
16.5 (l)	Functions/ Conferences may be organized every year under the Town Official Language Implementation Committee so that awareness and favourable atmosphere could be created in favour of the usage of Official Language.	This recommendation has been accepted.
16.5 (m)	Official Language Implementation Committees should be set up in all offices under Chairmanship of the Head of Offices and quarterly meetings of the Committees must be convened regularly. Progress in respect of complete and incomplete works done after the last meeting should be reviewed in the ensuing quarterly meeting.	This recommendation has been accepted.
16.5 (n)	Records should be maintained relating to the quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee and decisions taken in the meetings should be implemented solemnly and attentively.	This recommendation has been accepted
16.6 (a)	Cultural programmes/ seminars and "Kavi Sammelans" should be organized in the country as well as abroad, from time to time, so that Hindi could be popularized.	This recommendation has been accepted in principle. All the offices may organize cultural Programmes/ Seminars as per their resources.

16.6 (b)	Every Government Office should have libraries/ book-clubs equipped with simple, interesting and comprehensive books in Hindi. On occasion the readers should be encouraged so as to develop an interest in reading and writing Hindi. The amount of the rewards meant to encourage the use of Hindi should be enhanced. The minimum amount should not be less than Rs.1000/. The number of rewards should also be increased.	This recommendation has been accepted with the modification that all offices may spend their library grants on purchasing of Hindi Books as per the targets specified in the Annual Programme and encourage their employees to read these books. The issue of increasing the amount and number of prizes will be considered later.
16.6 (c)	To ensure that there should not be any dearth of books in Hindi in the field of Science & Technology, attractive rewards should be given to the authors who write originally in Hindi. Simultaneously, keeping in view the utility of the book, provision for appropriate royalty should be made.	This recommendation has been accepted. All Ministries/ Departments may take necessary action in this regard.
16.7 (a)	Department of Official Language should prepare a course to impart training for proficiency in Hindi to the officers/ employees who possess the working knowledge of Hindi, and appropriate steps be taken with the help of its Regional Implementation Offices.	This recommendation has been accepted in principle. Department of Official Language may prepare appropriate course of studies with the help of Ministry of Human Resource Development.
16.7 (b)	While granting permission to Private publishers for publishing Government Publications, a condition be imposed on them that they will not publish such publications only in English and it should be made mandatory for them to publish these publications in Hindi and English in diglot form.	This recommendation has been accepted with the modification that all Government publications should be printed in diglot form, as far as possible.
16.7 (c)	More Hindi posts are required to be created at each level.	This recommendation has been accepted. All Ministries/ Departments and offices are directed to comply with the orders issued regarding minimum Hindi posts, keeping in view the relevant orders of the Government issued in this regard.
16.7 (d)	In service training for the officers of the rank of Under Secretary and above for enhancement of their managerial skills should be conducted in Hindi.	This recommendation has been accepted with the modification that all in-service Training courses be conducted primarily in Hindi and secondarily through mixed medium.

16.7 (e)	To motivate the officers serving in Central Services etc., to do their work in Hindi, eminent Hindi scholars of Universities or other eminent personalities, who could present their subject in Hindi, be invited at specially organized workshops.	This recommendation has been accepted. Prominent Hindi Scholars and eminent persons may be invited to Hindi workshops.
16.7 (f)	Specific targets in respect of dictation in Hindi or for other work to be done in Hindi by the officers may be included in the Annual Programme of the Department of Official Language and it should be made mandatory for them to keep a record of this work and it should be ensured that the same is reviewed at Headquarter/ Ministry level.	This recommendation has been accepted with the modification that officers provided with stenographic assistance may utilize their services fully. Department of Official Language may prescribe targets in the Annual Programme for giving dictation in Hindi by the officers.
16.8 (a)	Legislative Department, while according priority to the work of providing training for original drafting in Hindi, should start it in a time-bound manner within 3 months, so that legislative drafting could be done originally in Hindi.	Similar recommendation was also made in 5 th Part of the Report of the Committee of Parliament on Official Language at recommendation No.10. The recommendation was accepted in principle and orders were issued to the effect that "Legislative Department of the Government of India should make arrangements for imparting training to legal experts/draftsmen for drafting legal materials originally in Hindi." Legislative Department may take necessary action in the light of the recommendation.
16.8 (b)	For this purpose, training should be completed within a span of six months to one year. Work of legislative drafting in Hindi should commence within 2 years from the completion of training. Setting up of an Institute for this purpose may be considered.	This recommendation is accepted in principle. Legislative Department may prepare a time bound action plan for this purpose.
16.8 (c)	Special incentive may be given to those, who undertake drafting in Official Language Hindi.	This recommendation has not been accepted, as draftsmen are regular government officials.

16.8 (d)	Article 348 of the Constitution may be amended to enable the Legislative Department to undertake original drafting in Hindi.	
16.8 (e)	After the amendment of Article 348 of the Constitution, High Courts/ Supreme Courts should be asked to start delivering their judgements and decrees, etc. in Hindi so that large number of Government Departments, who are carrying out judicial/ quasi-judicial functions, could be able to deliver orders in Hindi. At present, these departments are unable to pass orders in Hindi, because the appeal against their orders in High Courts/ Supreme Courts would have to be conducted in English.	[d]&[e]: These recommendations may be referred to the Legislative Department with the directions to obtain the views of Law Commission of India and thereafter intimate their considered opinion on these recommendations. Final decision will be taken accordingly.
16.9 (a)	Any person from outside the Government be appointed to the post of Hindi Advisor to the Government of India; who would, not only be a permanent invitee to the Committee of Parliament on Official Language; but also be a permanent member of the Kendriya Hindi Samiti. The services of any scholar or any experienced person, as also one associated with the propagation of Hindi, should be taken for this purpose.	This recommendation is under consideration.
16.9 (b)	To ensure that the daily routine work in Government Offices originates in Hindi, senior level officers may also be imparted training in Hindi. The Department of Official Language should organize workshops for Joint Secretaries and other senior officers. After organizing Hindi workshops for Ministries/ Departments, similar workshops may also be organized for the senior executives of Attached/ Subordinate Offices, in order to change their attitude towards work in Hindi and to ensure that these officers take part in these workshops, their attendance should be made mandatory.	This recommendation has been accepted.

16.10	<p>In order to ensure the availability of various Codes,, Rule Books and procedural literature relating to administrative and financial matters of the Central Government Offices along-with the publications of other Ministries/ Departments in Hindi, the Committee of Parliament on Official Language recommends as under:</p>	
16.10 (1)	<p>Provision should be made to seek Government permission for getting the copyright by private publishers before printing of the Government publications/ material; and if such a provision already exists, a condition to the effect that the publication shall be both in Hindi and English should be included therein before the permission is accorded by the Government or any office/ department. If, on the basis of size etc, printing of any book/ compilation in ciglot form is not feasible, in such a situation a special mention should be made on the cover page of the English edition that the Hindi version of this edition is also available with the publisher/ distributor.</p>	<p>This recommendation has been accepted with the modification that all Government Publications may be published in diglot form, as far as possible.</p>
16.10 (2)	<p>An additional Cell may be set up under the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language by the Government of India and be assigned the following responsibilities:-</p> <p>[a] This cell will ensure proper coordination among the original writing, translation and the publication work of Government publication of all Ministries/ Departments and will also ensure easy availability of this published literature.</p> <p>[b] To tackle the scarcity of Hindi publications in the Ministries/ Departments/ Institutes relating to Research, Science and Technology field, the cell may draw a panel consisting of experts/ educationists of these areas and will ensure original writing as well as standardized translation in Hindi of the required material available in other languages.</p>	<p>[a] to [e]: These recommendations are under consideration.</p>

	<p>[c] This cell will compile a list classifying all the Government publications and will bring out the same regularly. In addition to this, it will also bring out a monthly bulletin providing fresh information regarding the availability of new Hindi publications and the sources from where these are available.</p> <p>[d] For this purpose the cell will create its own website and will update it with information relating to various useful software available in the market for expansion and propagation of Hindi along-with the availability of various Government Hindi publications.</p> <p>[e] In order to ensure the availability of Hindi publications in the Ministries/ Departments/ Undertakings, this cell will provide all sorts of help and guidance.</p>	
16.10 (3)	For effective compliance of the Official Language Policy, the Committee recommends that the Department of Official Language should bring up updated edition of the Rule Books regarding use of Hindi, biennially, and ensure appropriate planning of its circulation and distribution so that the orders and the compilations issued from time to time by the Department of Official Language become available in all the large and the small offices of the Union Government.	This recommendation has been accepted.
16.10 (4)	The Committee would like to suggest that Government should undertake an in-depth study of the present system of the Publications Department and ensure appropriate steps to make it accountable to the Official Language Policy.	This recommendation has been accepted. Department of Official Language and the Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting may take appropriate action in this regard.
16.10 (5)	Arrangement of early publication of new/ revised editions of the government publication duly incorporating the amendments/ alterations carried out from time to time should be ensure on the pattern of Private Publications. According to information received, the printed government compilations and their amended/ updated editions are printed after a gap of years, that is why	This recommendation has been accepted. All Ministries may ensure appropriate action in this regard on priority.

	they fail to prove useful and consequently the government offices wholly depend upon the private publications. The solution to this situation must be explored and a certain time limit should be fixed for printing of the updated compilations.	
16.10 (6)	To ensure easy reading of these publications, appropriate type-set, cover and other pages etc. should be on good quality paper; selected fonts for emphatic printing be used; keeping in view their utility publications may be in different sizes; a professional approach is required to be taken in the present policy.	This recommendation has been accepted. All Ministries, particularly Ministry of Urban Development, Directorate of Printing and the Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting may ensure action in this regard on priority.
16.10 (7)	For making the government publications more accessible the number of sales counters should be increased and by making necessary change in the present policy the assistance of private book seller/ agencies may be sought for this purpose. Necessary co-ordination in Hindi translation, publications and the distribution of government literature may be established so as to ensure their availability in every Government Office right from the Ministries to the smallest office.	This recommendation has been accepted. All Ministries, particularly Department of Official Language and Controller of Printing, Ministry of Urban Development may ensure action in this regard on priority.
16.11 (a)	The committee has found that Hindi is being taught up to middle standard in one or the other way in almost all the states. The Committee recommends that this must be continued.	This recommendation has been accepted. Ministry of Human Resource Development may take appropriate action for the continuation of teaching of Hindi in secondary schools in non-Hindi speaking States.
16.11 (b)	Extensive efforts should be made in order to raise the level of Hindi in Non-Hindi speaking Union Territories.	This recommendation has been accepted. Ministry of Human Resource Development may take necessary action in this regard.
16.11. (c)	The education of Hindi in all the States and Union Territories situated in Region 'B' and 'C' be started from the primary level and be made compulsory up to Class Tenth. Passing Hindi subject obtaining prescribed marks be made mandatory. Arrangements should be made to teach Hindi as an optional subject up-to class	This recommendation has been accepted in principle. Education is included in the concurrent list. Hence, Ministry of Human Resource Development may take appropriate action after consultation with the State Governments in this regard.

	12 th level. Appropriate provisions for Hindi Education be made in the next Five Year Plan. For this purpose, necessary assistance to the State Govts. Should be provided by the Central Govt.	
16.11 (d)	Present arrangement of Language(s) relating to mutual correspondence among the State Governments situated in Region 'A', 'B' and 'C' States and the Union Government should be continued.	This recommendation has been accepted.
16.11 (e)	Hindi Departments should be opened for Higher Education and Research in the Universities of Non-Hindi speaking States, where no such Hindi Departments are in existence. In this regard initiative should be taken by the Ministry of Human Resources Development and the University Grants Commission.	This recommendation has been accepted in principle. Ministry of Human Resource Development may take necessary action to implement this recommendation.
16.12 (a)	In the context of disinvestment, the Committee recommends that the status-quo with regard to the Official Language policy should be maintained in these enterprises irrespective of the government's large or small shareholding in them.	Department of Official Language may consult with the Ministries regarding this recommendation.
16.12 (b)	Correspondence in Hindi with the Govt. should be made mandatory for those MNC's as well as Domestic Companies who use Hindi to publicise and promote the sale of their products. At the same time the Government should also respond in Hindi.	Department of Official Language may consult with all concerned.
16.12 (c)	The description on Indian goods meant for sale in foreign countries should compulsorily be given in Hindi along-with the foreign languages.	This recommendation has been accepted in principle.
16.13 (a)	Since the officers & employees, using the computer in English can be trained for using the computer in Hindi, within a maximum period of two weeks, therefore, all the officers/ employees should be imparted training to use the computer in Hindi, within a period of two years.	All Ministries may make efforts to implement this recommendation.

16.13 (b)	An 'Information Technology mission' should be set up under the aegis of the I.T. Ministry to undertake R & D projects in Hindi software. This "I.T. Mission" should also coordinate with other Government of India Departments using complex network systems viz. Railways, Posts, Banking, Telecom, Civil Aviation, Power etc. so that they can also develop their specialized software packages in Hindi.	This recommendation has been accepted. Ministry of Communications and Information Technology may take necessary action in this regard.
16.13 (c)	The I.T. Ministry should also play a nodal role to ensure that all Govt. of India Departments are introducing and using only that software which can be used in Hindi.	This recommendation has been accepted. Ministry of Communications and Information Technology may take necessary action in this regard.

Order

Ordered that a copy of this resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice-President Secretariat, the Cabinet Secretariate, the Prime Minister's Office, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat, the Registrar General of the Supreme Court of India, the University Grants Commission, the Law Commission of India, the Bar Council of India etc.

This Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. L. GUPTA
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
New Delhi-11, the 8th July 2005
(ARCHAEOLOGY)

No. F.9/4/2004-EE(CABA).—In pursuance of the Government of India, Archaeological Survey of India's Resolution No. F.9/4/2004-EE(CABA) dated 29.03.2005 the under mentioned Members have been approved by the competent authority to be the Members of Central Advisory Board of Archaeology.

1. Prof. Suraj Bhan,
Former Prof. of Archaeology,
Kurukshestra University,
1817, H.B. Colony, Sector 1, Rohtak (Haryana).
2. Prof. D. Mandal,
Former Prof. of Archaeology,
Allahabad University,
9/33, Lowther Road,
Georgetown, Allahabad (U.P.).

3. Shri Sitaram Roy,
Former Director, Archaeology,
Govt. of Bihar,
Nehru Nagar,
Patna (Bihar).

C. BABU RAJEEV
Director General